The Indian Express (Express News line) 5 Feb. 2003 P1

Last of homes in Vishwas 'factory' Nagar

PUJA BIRLA
NEW DELHI, FEBRUARY 4

THE air in Vishwas Nagar and Karawal Nagar smells of metal. The water used for washing copper, iron and tin seeps to groundwater. The two colonies are among the 24 residential areas where "light and non-hazardous industries" will be allowed.

The change in land use means residents can legally pollute air and water. Vishwas Nagar in east Delhi has pigeon-hole factory units and is called the Capital's copper *mandi*. Printing presses here deal in reams of paper and units beat metal sheets and cut plywood to size.

The industries wouldn't have been incongruent had Vishwas Nagar been an industrial zone. But in this residential colony, people run factories and live above them. Erstwhile governments have forced the "compromise" upon us, residents say.

"When I came here in 1988, there were no industries. A few people set up industries and the government turned a blind eye. By 2000, land here was selling for almost Rs 15,000 per square yard. When industries were shut, prices fell to Rs 5,000 per square yard. Prices are expected to soar once the land use is changed," says O P Sharma, a resident and a copper wires dealer.

Residents are so keen for this alteration that leaders, sensing the mood, have plastered handbills declaring that the "fight will continue till the area is declared industrial".

"More than 70 per cent of Vishwas Nagar is industrial. People live here but what's the point of running factories surreptitiously when everyone is doing it?" asks Manoj Jain, a factory owner. His unit is on the ground floor and he lives with his family on the first and second floors of the building.

Metal scrap outside a unit. B B YADAV

Water and electricity are charged as per industrial rates. "We don't pay house tax. Industries have been allowed to proliferate. Might as well legitimise the zone," says Jain.

In Karawal Nagar, northeast Delhi, industries run behind closed gates. Questions are looked at with grave suspicion. "More than 80 per cent of this place has factories. We live here and have our factories here. But no government official can touch us. It takes only 10 minutes to remove any trace of a factory. We always come know of a raid beforehand," says a smug Naresh Gupta.

'Industries will be Capital's death'

ESHA ROY
NEW DELHI, FEBRUARY 4

TURNING 24 residential areas to industrial zones would be fatal for Delhi, say town planners and environmentalists.

Delhi will become an industrial zone and pollution control measures will remain on paper, said Ranjit Kumar, amicus curiae to the Supreme Court in the Yamuna case.

"The policy cannot be passed against public opinion. The warning that industries will have to follow pollution norms is an eyewash," he says.

Experts say the policy is against law and Supreme Court orders. The court in 2000 had asked the Delhi Government to relocate all polluting industries. The Delhi Development Authority in an affidavit in the Supreme Court has admitted that 377 illegal commercial units had illegally been set up in industrial plots.

H D Shourie of Common Cause said: "The policy will ruin Delhi. Water supply, waste management and power will be thrown out of gear. Delhi has more than 1 crore people and industries will attract more people."

"What becomes of the residents? Who is to check that the G and H category industries do not begin to function here?" said Sunita Narayan, Director, Centre for Science and Environment.

"No government has ever been able to limit industrial growth. The policy is same as regularising DDA violations. It is condoning illegal activities in hindsight," said Ravi Aggarwal, director, Shrishti.

गुरुवार को कोटला मैदान में भाजपा ने उद्यमियों की रैली की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल खुराना, मेवाराम आर्य, लालबिहारी तिवारी और पवन शर्मा भी मौजूद थे। फोटो-रवि बत्रा

गरीबों को इंसाफ दिलाएगी भाजपा: खुराना

जनसत्ता
5 Feb. 2003
P. 3

भाजपा की चेतावनी रैली में दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन का एलान

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, ४ फरवरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने कहा कि दिल्ली के गरीबों, मेहनतकशों और कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। वे आज फिरोजशाह कोटला में चेतावनी रैली में बोल रहे थे। रैली में प्रस्ताव पास कर सरकार के संरक्षण में निजी ठेकेदारों द्वारा बिजली सप्लाई के नाम पर लूट की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई।

खुराना ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों, पुनर्वास बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ठेकेदारों ने नकली रसीदों से जमा की गई करोड़ों की रकम या तो जल्दी ही उन्हें वापस दिलाई जाए या फिर इस रकम को दिल्ली की कांग्रेस सरकार सरकारी खजाने में जमा कराए। उन्होंने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा इन गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी। इसके तहत धरने प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि १९९९ में कांग्रेस के शासन में एक हजार से ज्यादा सिंगल प्वाइंट बिजली सप्लाई के नाम पर कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों और असामाजिक तत्वों को ठेकेदार नियुक्त किया गया था। जो अब तक चार साल में दिल्ली की गरीब जनता से करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास शुल्क के नाम पर प्रति परिवार छह हजार रुपए वसूले गए। बिजली की दरें भी चार रुपए प्रति यूनिट की दर से वसूली जा रही हैं। यहां तक बिल देरी से जमा करने पर ठेकेदारों ने ५० रुपए प्रति दिन की शर्त लगाई है।

खुराना ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को जल्द नियमित किया जाना है। इन बस्तियों में रहने वालों पर दोबारा विकास शुल्क की मार पड़ेगी रैली को केंद्रीय श्रम मंत्री साहिब सिंह, सांसद लाल बिहारी तिवारी, महामंत्री पवन शर्मा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल रतावाल महामंत्री महेंद्र नागपाल, मूलचंद चावला, प्रदेश मंत्री जगदीश ममगाई, पूर्व विधायक मेवाराम आर्य, अनधिकृत कालोनी प्रकोष्ठ अध्यक्ष और पूर्व उपमहापौर राजेश गहलोत, पुनर्वास बस्ती के अमृतलाल, चांद राम पूर्व उद्योग मंत्री हरशरण सिंह बल्ली, ओपी बब्बर, धर्मदेव सोलंकी और प्रदेश मंत्री मनोज शौकीन ने भी संबोधित किया।

केंद्रीय श्रम मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली के गरीबों पिछड़ों व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसान किस्तों पर बिजली मुहैया कराई गई थी। अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों को निश्चित शुल्क देकर डेढ़ रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से बिजली की दरें ली जानी थी।

साहिब सिंह ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार दिया गया था। जिसे कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज उन पर अनिश्चितता की तलवार लटक रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल रतावाल ने कहा कि बिजली के बिल जमा करने के नाम पर कांग्रेस सरकार ठेकेदारों से लूट करवा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों और उनके सरकार के दलालों के खिलाफ प्रदेश भाजपा एक हो चुकी है। और जल्दी ही अगर कांग्रेस सरकार ने पीड़ित लोगों को न्याय नहीं दिया तो प्रदेश अध्यक्ष खुराना की अगुआई में आंदोलन शुरू होगा।